लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4308

19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

विनिर्माण में स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए सहायता

4308. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय की बजट 2025-26 की पहलों, जैसे वस्त्र विनिर्माण में स्वच्छ प्रौद्योगिकी के लिए सहायता में पारंपरिक हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कारीगरों के लिए अनुकूल प्रावधानों का अभाव है; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय किस प्रकार आईएमएफ/विश्व बैंक की सिफारिशों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने और आजीविका बढ़ाने के लिए साक्ष्य-आधारित समावेशन मैट्रिक्स और नीतियों को एकीकृत करेगा?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी कारीगरों सहित वस्त्र और हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक क्षेत्र में विनिर्माण को समर्थन देने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में निम्नलिखित सहित कुछ उपाय शुरू किए हैं:

1. कृषि-वस्त्र, चिकित्सा वस्त्र और जियोटेक्सटाइल जैसे तकनीकी वस्त्र उत्पादों के प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, पूर्ण छूट प्राप्त वस्त्र मशीनरी की सूची में दो और प्रकार के शटल-रहित करघों को शामिल किया गया है। "10% या 20%" से "20% या ₹ 115 प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो" तक की नौ टैरिफ लाइनों के अंतर्गत आने वाले बुने हुए वस्त्रों पर बीसीडी दर भी लागू की गई है।

2. **हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा**: हस्तशिल्प के निर्यात को सुगम बनाने के लिए, निर्यात की अवधि छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई है, जिसे आवश्यकतानुसार तीन महीने और आगे बढ़ाया जा सकता है। शुल्क-मुक्त आगतों की सूची में नौ वस्तुओं को भी जोड़ा गया है। वास्तविक निर्यातकों द्वारा शुल्क-मुक्त आगतों से निर्मित हस्तशिल्प के निर्यात की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई है, जिसे 3 महीने और आगे बढ़ाया जा सकता है।

3. **कपास उत्पादकता मिशन:** 5-वर्षीय मिशन का उद्देश्य कपास की खेती की उत्पादकता और सस्टेनेबिलिटी में महत्वपूर्ण सुधार लाना तथा अतिरिक्त लंबे रेशे वाली कपास किस्मों को बढ़ावा देना है।

मंत्रालय विभिन्न योजनाओं जैसे समर्थ, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी), राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) आदि को कार्यान्वित करते समय साक्ष्य-आधारित समावेशन मैट्रिक्स और नीतियों को एकीकृत करता है।

******